नवीन कुमार मिश्र, पटना सुशासन और न्याय के साथ विकास के नारे को लेकर नीतीश सरकार सत्ता में आई। बीते वर्षो में विभिन्न स्तर पर विभिन्न तरह के काम भी हुए। अब सरकार सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारने में जुटी है। बेहतरीन प्रशासन, उसी तरह डिलीवरी सिस्टम, गरीबों के विकास से आच्छादित बिहार जैसे एजेंडे को लेकर सेंटर फार गुड गवर्नेस सोसाइटी को जमीन पर उतारने की तैयारी आरंभ कर दी गई है। इसमें मुख्य सचिव की भांति वेतन सुविधा प्राप्त महानिदेशक सह कार्यपालक निदेशक, 80 हजार से एक लाख रुपए के वेतन पर निदेशक के साथ विभिन्न तरह के पदों का सृजन किया गया है। प्रशासी पदवर्ग समिति की मंजूरी के बाद कैबिनेट से मंजूरी की तैयारी है। उद्देश्य प्रशासनिक सुधार-प्रशासनिक तंत्र की बिहार में मजबूतीकरण के लिए सतत परामर्श एवं बौद्धिक विकास के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की बौद्धिक विचारक संस्था की स्थापना 8नवनिर्माण को दृष्टिपथ में रखते हुए प्रशासन क सर्वोत्तम व्यवस्था, प्रशासन एवं सेवा प्रदान करने की व्यवस्था पर शोध एवं उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन 8मुख्य अधिनियम व्यवस्था में नीतिगत मामलों पर पुनर्विचार एवं इन्हें अद्यतन करने के लिए बिहार सरकार को नीति निर्धारण के स्तर पर समर्थन एवं सहायता प्रदान करना शासी निकाय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शासी निकाय काम करेगी। जिसमें मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, महानिदेशक बिपार्ड, प्रधान सचिव वित्त, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन, ख्याति प्राप्त एकेडमिक इंस्टीच्यूट के अध्यक्ष जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान या पटना स्थिति विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान तथा महानिदेशक गुड गवर्नेस सोसाइटी। प्रबंधन समिति महानिदेशक गुड गवर्नेस सोसाइटी की अध्यक्षता में कमेटी होगी जिसमें निदेशक सुशासन, उप निदेशक वित्त और उप निदेशक कार्मिक सदस्य होंगे। अब गुड गवर्नेस सोसाइटी करेगी सुशासन साकार

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति